सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-568**
24/12/2018

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की अहम बैठक

पटना 24 दिसम्बर 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में पटना एयरपोर्ट के विशिष्ट अतिथि कक्ष में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की अहम बैठक आयोजित हुयी। बैठक में देश के आर्थिक विकास को और अधिक तेज करने के लिए निचले स्तर पर जिलों की भूमिका को चिह्नित करने के साथ ही जिला स्तर पर इज ऑफ डुइंग बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। कैसे जिला स्तर पर जी0डी0पी0 को बढ़ाया जाय, इस पर भी चर्चा की गयी।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर के करीब हो जाने का अनुमान है। 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिये ये जरूरी है कि सतत् विकास की गति को बरकरार रखा जाय। इसके साथ ही जिलों के स्तर पर भी योजनाओं की जमीनी तरक्की पर ध्यान दिया जाय। आई0आई0एम0 एवं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को इसकी जवाबदेही दी गयी है, जो चयनित जिलों के लिये जिला प्रशासन एवं संबंधित हितधारकों के साथ नीतियों के क्रियान्वयन पर कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के पाँच राज्यों के छह जिलों– मुजफ्फरपुर (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश), सिन्धु दुर्ग (महाराष्ट्र), रत्नागिरी (महाराष्ट्र) एवं सोलन (हिमाचल प्रदेश) का चयन कर प्रत्येक जिलों के जी0डी0पी0 का आकलन कर उसे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत पर बल दिया है।

बैठक में मुजफ्फरपुर में फिश फार्मिंग, हनी प्रोड्युसिंग, कृषि, सेवा, उद्योग, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग जैसे 8 अलग–अलग क्षेत्रों का चयन कर काम शुरू किया गया है। बैठक के दौरान आई0आई0एम0 के प्रोफेसर ने बताया कि दो चरणों में काम शुरू किया गया है और इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण अब खत्म होने वाला है। द्वितीय चरण नौ माह का है, इस दौरान चयन किये गये क्षेत्रों के सन्दर्भ में विभिन्न जिलों के लिए आंकड़े तैयार किये जायेंगे। साथ ही साथ इन जिलों के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गयी है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी तरीके से हो इसके लिए आई0आई0एम0 के लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता करेंगे। आई0आई0एम0 के एक्सपर्टस ने बताया कि मुजफ्फरपुर की प्रतिवर्ष इकोनॉमी 10 हजार करोड़ की है, जो करीब साढ़े चार प्रतिशत की दर से ग्रो कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुजफ्फरपुर का आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और इसके 8 प्रतिशत के करीब करने को लेकर अगले तीन–चार वर्षों में कृषि, सेवा, फिश फार्मिंग, डेयरी, गारमेंट्स, समेत लघु एवं मध्यम उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिये रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक के दौरान एक्सपर्टस ने बताया कि को–ऑपरेटिव की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के साथ ही उसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि सही लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके।

केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेवा जैसे क्षेत्रों में निचले स्तर पर काम हो ताकि देश की इकोनॉमी ग्रो करे। उन्होंने कहा कि जो किसान खेती नहीं करना चाहते हैं उन्हें स्किल

डेवलपमेंट के काम में लगाया जाए। जिलों में भी इज ऑफ डूइंग जल्द शुरू हो ताकि बड़े पैमाने पर निवेश के इच्छुक नव उद्यमियों को फायदा मिल सके। हम इसे सभी जिलों में शुरू करना चाहते हैं। पायलट योजना के तहत सिर्फ छह जिलों का चयन कर काम करने से नहीं होगा बल्कि और जिलों को भी आने वाले समय में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जाए ताकि 3 से 4 प्रतिशत तक जी0डी0पी0 बढ़ाई जा सके।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपलोगों ने मुजफ्फरपुर में रिसर्च कर जिन क्षेत्रों का चयन किया है वह ठीक है लेकिन वहां के लेदर सेक्टर की भी स्टडी करेंगे तो कई चीजें निकलकर सामने आयेंगी। उन्होंने कहा कि यहॉ की लेदर की क्वालिटी काफी अच्छी है। यहॉ लेदर सेक्टर में काफी पोटेंशियल भी है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से ही लेदर कलेक्ट होकर चेन्नई जाता है। इसके अलावा शाही लीची और लहठी भी इस क्षेत्र की पहचान है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव, विधायक श्री अरुण सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री के०के० पाठक, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, वित्त (व्यय) विभाग के सचिव श्री राहुल सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित राज्य सरकार के अन्य वरीय अधिकारी, आई0आई0एम0 के एक्सपर्टस, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अधिकारी उपस्थित थे।

******